It is a reflection not on me, but on those who have admitted that question.

सवाल एक है या दो हैं यह नहीं है। सवाल यह है कि अगर किसी के साथ अन्याय होता हो, भेद-भाव होता हो तो उसकी बात को उठाने की यहां पर इजाजत है या नहीं है?

श्री सभापति . एक का भी उठा सकते हैं। पांच का भी उठा सकते हैं। That is all right.

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI: 1 register my protest

*465. *[The questioners (Shri Kalraj* Mishra and Shri *Lal K.* Advani) *were absent. Tor answer* vide cols, infra]

*466. *[The questioner (Shri M. R. Krishna) was absent. For answer* vide col. infra]

Appropriation Funds for Adivasi Sub-Plan

•467. SHRI PANDURANG DHARMAJI JADHAV; Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have allocated separate funds for Adivasis and prepared the Adivasi sub-plan;

(b) whether Government are aware that funds allocated for the Adivasi sub-plan are not utilised for the development of Adivasis;

(c) whether Government are also aware that some of the funds allocated for Adivasis are being diverted to different other projects in Thane District (Maharashtra);

(d) what are the other places and projects in the different States where the funds allocated for the sub-plan for Adivasis have not been diverted; and

(e) whether Government of India propose to ensure that the funds al-.-located for the sub-plan are properly utilised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Government of India provides Special Central Assistance to 1? States and 2 Union Territories for implementing programmes of Tribal Sub-Plan. Major share of funds for implementation of the Tribal sub-Plan comes from the State Plan resources. The 17 States and 2 Union Territories prepare Tribal (Adivasi) sub-Plans.

(b) According to reports received by Government funds allocated for Tribal sub-Plan are utilised for Tribal development.

(c) It has been intimated by the Government of Maharashtra that funds allocated for Adivasis are not being diverted to other Projects. It has further been clarified that proportionate provision is made from Tribal sub-plan funds for projects in Thane District.

(d) As per information available with the Ministry Tribal sub-plan funds are not diverted for other purposes.

(e) In the guidelines issued from time to time and also in discussions held with the State representatives, ways and means of ensuring proper utilisation of funds allocated have been emphasised. These are reviewed in various forums from time to time. ••

श्री पांडुरंग धर्माजी जाधव : सभापति जी, जो सवाल मैंने पूछा कि आदिवासी सब प्लान का पैसा जो आदिवासी एरिया डेवलपमेंट के नाम पर दूसरे प्रोजेक्ट्स पर खर्च किया गया है जैसे कि तीन साल पहले

थाना डिस्ट्रिक्ट में भारंसा केनाल प्राजैक्ट के लिए आदिवासी सब प्लान म पैसा दावचरी डेरी डेवलपमेंट में तमाम खर्च हुआ। इसमें आदिवासियों को तो केवल गोबर उठाने के कार्य में लगाया जाता है और भारसा केनाल जो है उसमें आदिवासी सिचाई में आते नहीं। तो यह पैसा जो आदिवासियों के नाम पर खर्च किया गया है इसकी क्या सरकार को जानकारी है?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: This is about tribal sub-plan. Upto the Sixth Plan period it was so devised that all schemes under this plan were area development schemes. In the Sixth Plan we have changed them into family oriented ones and when more than 51 per cent of the command area comes under the tribal belt, then the contribution is made under tribal sub-plan. And, Sir, the two schemes which the honourable Member has mentioned come within the tribal belt and more than 50 per cent area of the command area is in the tribal belt and. therefore, the quantification is made towards the tribal sub-plan.

श्री पांडुरंग धर्माजी जाधव : मेरा यह कहना है कि जो पैसा 'सब लान' और भारसा प्रोजक्ट कैनाल में आदिवासियों के विकासार्थ रखा गया है, उमक विकास पर खर्च नहीं किया गया है। आदिवासियों के विकास के नाम पर करोड़ों रुपया व्यय दिखाया जाता है लेकिन सत्य यह है कि उनको पानी तक नहीं मिलता है

श्री योगेन्द्र मकवाणा : ये दोनों एरियाज आदिवासियों के हैं। आदिवासियों की जमीन वहां पर है और इसलिए उनको पानी मिलेगा।

श्री जी० स्वामी नायक मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा हालांकि कि राज्यों में आदिवासी सब प्लान के लिए सरकार का कई करोड़ों रुपयों में खर्च आता है और भी कई जगह यह शिकायत है कि ट्राईबल सब प्लान में धनराशि बराबर खर्च नहीं होती है, इसलिए क्या ट्राईबल सब प्लान के अलावा जो आदिवासी जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं उनके लिए कोई सरकार के पास प्रोपोजल है? दूसरा जो करोड़ो रुपया केन्द्रीय सरकार के द्वारा आदिवासियों के लिए खर्च होता है क्या सरकार का उसकी देखरेख के लिए कोई कारपोरेशन या किसी एजेंसी के बनाने का इरादा है?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : श्रीमान्, इसमें डाइवर्सी फिकेशन नहीं हो सकता है क्योंकि बजट में मेजर हैड के नीचे और सब हेड भी होते हैं, तो उस हैड के अन्दर ही पैसा खर्च किया जायेगा। पहाड़ों में जहां प्रिमिटिव ट्राईब्स है उसके लिए स्पेशल स्कीम है। इसलिए जैसा आनरेबुल मेम्बर ने बताया तो उस प्रिमिटिव ट्राईव के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है वे उसमें उसका फायदा उठा सकते हैं।

जहां तक जो सेकेण्ड क्वेश्चन किया और उसके लिए जो मशीनरी की बात की तो एक मानीटरिंग सेल हम यहां लगा रहे हैं। अभी भी मानीटरिंग तो होती है लेकिन उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए एक स्पेशल मानीटरिंग सेल होम मिनिस्ट्री में बन रहा है।

MR. CHAIRMAN: All right. Next question.

*467A. [The questioner (Shri *Sun der Singh Bhandari) was absent. For answer* vide *col. infra]*.

MR. CHAIRMAN: Now, the next question. Question No. 468.